डी1लियट सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम:

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र

और अन्य - उत्तरदाता

सीडब्ल्यूपी. 2010 की संख्या 716एल

18 नवंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-कला, 226-3 वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश-याचिकाकर्ता प्रथम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ और सफल घोषित किया गया-दूसरे वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया गया-याचिकाकर्ता ने स्नातक परीक्षा में 45% से कम अंक प्राप्त किए-पात्र नहीं एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए -प्रवेश रद्द करना - विश्वविद्यालय कभी भी प्रवेश को मंजूरी नहीं दे रहा है और याचिकाकर्ता की पात्रता के बारे में आपत्ति उठा रहा है - विश्वविद्यालय ने कॉलेज के प्राचार्य से स्पष्टीकरण भी मांगा है -विनियमन की याचिका -आकर्षित नहीं -याचिकाकर्ता को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे अन्यथा बड़ी संख्या में व्यक्तियों का अधिकार नष्ट हो जाएगा - चूंकि याचिकाकर्ता ने कोई गलत बयानी नहीं की है, इसलिए, कॉलेज को इन सभी वर्षों के लिए ली गई पूरी ट्यूशन फीस वापस करने और उसे रुपये की दर से मुआवजा देने का निर्देश देने का एक अच्छा मामला बनता है। याचिकाकर्ता के जीवन और करियर को बाधित करने के लिए तीन साल की कुल अवधि के लिए 50,000 प्रति वर्ष।

माना गया कि याचिकाकर्ता का प्रवेश उचित विचार के बाद रद्द कर दिया गया है क्योंकि वह प्रवेश पाने के लिए पात्र नहीं था और जाहिर तौर पर कॉलेज ने एक अयोग्य व्यक्ति को प्रवेश देने के लिए याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत की है। यदि ऐसे अयोग्य उम्मीदवारों के प्रवेश को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो यह एक धोखाधड़ी होगी और कॉलेजों के पास अपने पसंदीदा को विचार या अन्यथा स्वीकार करने के लिए पात्रता शर्तों का उल्लंघन करने का लाइसेंस होगा। यदि कॉलेज की इस कार्रवाई को किसी भी तरह से स्वीकार कर लिया गया तो इससे स्तर में गिरावट आएगी।

(5) प्रस्ताव की सूचना जारी की गई और विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता के प्रवेश की वैधता के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई। जैसा कि अनुमान लगाया गया है, विश्वविद्यालय का रुख यह है कि याचिकाकर्ता एलएलबी में प्रवेश के लिए अयोग्य है। पाठ्यक्रम क्योंकि उन्होंने स्नातक परीक्षा में 45% से कम अंक प्राप्त किये थे। यह कहा गया है कि प्रतिवादी सं. 5-Collcgc ने याचिकाकर्ता को अयोग्य होते हुए भी प्रवेश दिया था और तदनुसार इस संबंध में दोष कॉलेज पर लगाया गया है। उस तिथि तक, कॉलेज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी और तदनुसार कॉलेज की ओर से उपस्थित वकील ने उत्तर दाखिल करने के लिए समय की प्रार्थना की। उस स्तर पर, कॉलेज की ओर से पेश वकील को यह प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था कि कॉलेज को अयोग्य होने के बावजूद याचिकाकर्ता को प्रवेश देने के लिए मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए। इस प्रकार, यह स्थिति पैदा हो रही है। कॉलेज ने तदनुसार एक जवाब दायर किया है जिसमें कहा गया है कि प्रवेश के बाद, प्रमाणपत्रों की फोटोस्टेट प्रतियों के साथ पंजीकरण रिटर्न सत्यापन और पंजीकरण के लिए विश्वविद्यालय को भेजा गया था। विश्वविद्यालय ने तब एक रोल नंबर जारी किया था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता प्रथम वर्ष एलएलबी के लिए उपस्थित हुआ। जिस परीक्षा का विश्वविद्यालय ने परिणाम भी घोषित कर दिया है. तदनुसार, कॉलेज याचिकाकर्ता को द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति देकर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराएगा।

(6) प्रारंभ में, याचिकाकर्ता को रोल नंबर जारी नहीं किया गया था और इसलिए वह दूसरे वर्ष की परीक्षा के तीन पेपर चूक गया, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता को अपने निवास पर एक रोल नंबर प्राप्त हुआ और तदनुसार वह शेष छह पेपरों में उपस्थित हुआ। उसके बाद, विश्वविद्यालय ने द्वितीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जिसके कारण वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

(7) विश्वविद्यालय के रुख के अनुसार, याचिकाकर्ता ने साफ हाथों से अदालत का रुख नहीं किया है। स्पष्ट रुख यह है कि याचिकाकर्ता के स्नातक परीक्षा में 45% से कम अंक हैं और इसलिए वह एलएलबी में प्रवेश के लिए अयोग्य था। अवधि। याची के बीए में 43.7 प्रतिशत अंक हैं। और एलएलबी के लिए प्रवेश। (प्रोफेशनल) 3 साल का डिग्री कोर्स इस प्रकार है:-

"कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या मास्टर डिग्री (2-वर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा, कुल मिलाकर कम से कम 45% अंकों के साथ (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 40% (एक वर्षीय डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम) जैसे. डी.पी. एड., एम.एड., बी.एड., बी. लिब.. एससी. आदि को स्नातक डिग्री के समकक्ष नहीं माना जाएगा)।

(8) विश्वविद्यालय के अनुसार, कॉलेज ने याचिकाकर्ता को संस्थान स्तर पर प्रवेश दिया था और यह प्रवेश किसी प्रवेश परीक्षा के आधार पर नहीं था। जब कॉलेज ने याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र उसके और उसके पिता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित करके भेजा, तो यह देखा गया कि योग्यता परीक्षा में उसके 45% से कम अंक थे और इस तरह वह एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अयोग्य था। याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए इस आशय के वचन का संदर्भ दिया गया है कि वह अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर कॉलेज में प्रवेश ले रहा है और विश्वविद्यालय द्वारा उसकी पात्रता की पुष्टि के अधीन है। याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया यह वचन इस प्रकार है:-

) कि मैं विश्वविद्यालय द्वारा मेरी पात्रता की पुष्टि के अधीन अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर कॉलेज में प्रवेश ले रहा हूं। यदि मुझे पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मेरा प्रवेश रद्द कर दिया जाता है, तो इसके लिए मेरा कोई दावा नहीं होगा।"

(9) तब यह खुलासा हुआ कि याचिकाकर्ता का प्रवेश 7 दिसंबर, 2007 को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता प्रॉस्पेक्टस में निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र नहीं था। इतना ही नहीं, यह भी देखा गया कि कुलपति ने भी गंभीर रुख अपनाया है। इसके बावजूद, कॉलेज ने याचिकाकर्ता को प्रथम वर्ष के लिए विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। इस पर विश्वविद्यालय ने प्राचार्य से विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने का कारण बताने को कहा। इस संबंध में 26 नवंबर 2008 का एक पत्र अनुलग्नक आर-एल/3 के रूप में उत्तर के साथ संलग्न है। इस प्रकार, यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसका प्रवेश रद्द कर दिए जाने के बावजूद कॉलेज ने याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। इसके बाद, विश्वविद्यालय ने मामले को डीन, अकादमिक मामलों और डीन, विधि संकाय की एक समिति के समक्ष रखा है। समिति को चाहिए था कि प्राचार्य का स्पष्टीकरण मांगा जाए। तदनुसार, स्पष्टीकरण मांगने वाला एक पत्र 31 मार्च, 2009 को जारी किया गया था। प्रिंसिपल ने 1 अप्रैल, 2009 को एक गोलमोल जवाब प्रस्तुत किया। फिर प्रिंसिपल को अपनी स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बीच, याचिकाकर्ता ने 25 मई 2009 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की प्रार्थना की। चूंकि मामला विचाराधीन था, इसलिए विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता को इस शर्त के साथ द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने का निर्णय लिया कि वह विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय से बाध्य होगा। बुरी आदत: कुलाधिपति ने अंततः निर्णय लिया कि याचिकाकर्ता को दिया गया प्रवेश नियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उक्त प्रवेश के लिए पात्र नहीं था। यह निर्णय कुलपति द्वारा समिति की सिफारिश/राय पर लिया गया, जिसमें कानून के डीन, शैक्षणिक मामलों के डीन और कानून विभाग के प्रोफेसर सुमन गुप्ता शामिल थे। तदनुसार, याचिकाकर्ता को तीसरे वर्ष की परीक्षा में प्रवेश लेने की अनुमति कभी नहीं दी गई। इस प्रकार, विश्वविद्यालय सारा दोष उस कॉलेज पर मढ़ देगा, जिसने याचिकाकर्ता को उसकी पात्रता की जांच किए बिना प्रवेश दिया था और यह गड़बड़ी पैदा की थी।

(10) जब 13 सितंबर, 2010 को रिट याचिका सुनवाई के लिए आई, तो विश्वविद्यालय के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता को अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय के वकील ने निर्देश देने के लिए समय देने की प्रार्थना की। इसके बाद वकील ने एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया जिसमें उस स्थिति और परिस्थितियों को समझाया गया जिसके तहत याचिकाकर्ता अंतिम परीक्षा में शामिल होने में कामयाब रहा।

(11) अब दायर अतिरिक्त हलफनामे में, विश्वविद्यालय ने इस तथ्य को दोहराया है कि कॉलेज ने याचिकाकर्ता को प्रवेश दिया था, हालांकि वह अयोग्य था और 7 नवंबर, 2007 के आदेश पर भरोसा करेगा, जिसके तहत यह प्रवेश रद्द कर दिया गया था। विश्वविद्यालय के अनुसार, याचिकाकर्ता को कभी भी छात्र के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था और उसे कोई पंजीकरण संख्या जारी नहीं की गई थी। फिर भी, कॉलेज ने याचिकाकर्ता को प्रथम वर्ष की एलएलबी परीक्षा देने की अनुमति दी थी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने एक समिति का गठन किया, जिसने पहले के आदेश को मंजूरी दे दी कि याचिकाकर्ता के प्रवेश को नियमित नहीं किया जा सकता है। यह भी खुलासा हुआ है कि कॉलेज के प्राचार्य ने पंजीकरण शाखा में एलएलबी तृतीय वर्ष में प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं किया था। याचिकाकर्ता फिर भी, प्रिंसिपल की मिलीभगत से, अन्य छात्रों के साथ अपना प्रवेश फॉर्म भेजने में कामयाब रहा। प्रिंसिपल ने ऐसा इस तथ्य के बावजूद किया कि उन्होंने स्वयं प्रमाणित किया था कि याचिकाकर्ता ने 75% व्याख्यानों में भाग नहीं लिया था और उसे एलएलबी में प्रवेश नहीं मिला था। तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम. इन परिस्थितियों में ही इसी असमंजस की स्थिति में याचिकाकर्ता को प्रोविजनल रोल नंबर जारी किया गया। तृतीय वर्ष की परीक्षा का परिणाम तदनुसार रद्द कर दिया गया है और इस संबंध में प्राचार्य को सूचित कर दिया गया है। उनसे यह भी बताने को कहा गया है कि याचिकाकर्ता का परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय को कैसे भेजा गया।

(12) एक हद तक, याचिकाकर्ता की यह शिकायत करना उचित प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने में काफी लंबा समय लिया और इस बीच याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी। टी वह: इस बीच याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी। इसलिए, याचिकाकर्ता यह तर्क देने का प्रयास करेगा कि वर्ष 2007 में प्रवेश रद्द करना हास्यास्पद है और इस स्थिति को बनाने के लिए विश्वविद्यालय को भी दोष से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

(13) याचिकाकर्ता के वकील श्री कृष्ण बनाम द कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरूक्षेत्र, (1) पर भरोसा करते हैं, जहां यह माना जाता है कि एक बार उम्मीदवार को सही या गलत तरीके से परीक्षा देने की अनुमति दे दी जाती है, तो वह क़ानून जो विश्वविद्यालय को वापस लेने का अधिकार देता है आवेदक की उम्मीदवारी अपने आप पूरी हो गई है और उम्मीदवार को बाद में किसी भी कमजोरी के लिए प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसे उम्मीदवार को उपस्थित होने की अनुमति देने से पहले देखा जाना चाहिए था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण की सहजता में सर्वोच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन मेरे विचार से, ये टिप्पणियां एक अलग संदर्भ में की गई थीं और इस मामले में पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता क्या थी? मुद्दा नहीं. सहजता से श्री कृष्ण (सुप्रा), अपीलकर्ता एक शिक्षक थे और विश्वविद्यालय एक पाठ्यक्रम चला रहा था और उन्होंने उन व्यक्तियों को सुविधा प्रदान की थी, जो शाम की कक्षाओं में भाग लेने के लिए सेवा में हैं। पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता का कोई मुद्दा नहीं था, बल्कि मुद्दा केवल परीक्षा में बैठने की पात्रता का था। इस संबंध में आग्रह किया गया कि आधार यह था कि किसी भी कारण से उम्मीदवारी वापस नहीं ली जा सकती और दूसरी बात यह कि विश्वविद्यालय की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी। मौजूदा मामले में ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है।

(14) याचिकाकर्ता का प्रवेश उचित विचार के बाद रद्द कर दिया गया है क्योंकि वह प्रवेश पाने के लिए पात्र नहीं था और जाहिर तौर पर कॉलेज ने एक अयोग्य व्यक्ति को प्रवेश देने के लिए याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत की है। यदि ऐसे अयोग्य उम्मीदवारों के प्रवेश को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो यह एक धोखाधड़ी होगी और कॉलेजों के पास पात्रता शर्तों का उल्लंघन करने का लाइसेंस होगा, ताकि वे या तो विचार-विमर्श पर या अन्यथा उनके पक्ष को स्वीकार कर सकें। यदि कॉलेज की इस कार्रवाई को किसी भी तरह से स्वीकार कर लिया गया तो इससे स्तर में गिरावट आएगी।

(15) सनातन गौड़ा बनाम बरहामपुर विश्वविद्यालय और अन्य (2) के मामले का संदर्भ भी याचिकाकर्ता के हित में मदद नहीं कर सकता है क्योंकि इस मामले में कानून पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए स्नातकोत्तर छात्रों के लिए किसी विशेष अंक की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें अभ्यर्थी (7) एआईआर 1976 एस.सी. 376"

(2) एआईआर 1990 एस.सी. 1075मामला। इस प्रकार, प्रवेश के लिए पात्र पाया गया, जो मौजूदा मामले में स्थिति नहीं है। इस मामले में भी कानून का अनुपात निर्धारित है. इस प्रकार, आशु सिंगला बनाम पंजाबी विश्वविद्यालय,

पटियाला और अन्य, (3) में वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस अदालत ने यह विचार किया है कि जब पात्रता के बारे में विश्वविद्यालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी और कोई आपत्ति नहीं थी याचिकाकर्ता द्वारा किसी भी गलत बयानी का सबूत, तो याचिकाकर्ता को भाग 1 और भाग II में अपनी पढ़ाई पर मुकदमा चलाने के लिए कम करने के बाद प्रतिवादी को पात्रता की दलील लेने से रोक दिया जाएगा। मौजूदा मामले में, विश्वविद्यालय ने कभी भी प्रवेश को मंजूरी नहीं दी और 1.1 जेयू पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता के बारे में आपत्ति उठाई थी। किसी भी स्तर पर, विश्वविद्यालय ने याचिकाकर्ता द्वारा रोक की याचिका उठाने के लिए इस मुद्दे को स्वीकार या अनदेखा नहीं किया था। बेशक, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट रूप से इस मुद्दे को भटकने देने में अच्छा आचरण नहीं किया है जिसका याचिकाकर्ता लाभ उठाने में सक्षम था। पहले अवसर पर, विश्वविद्यालय ने न केवल इस प्रवेश के संबंध में आपत्ति जताई बल्कि इसे रद्द कर दिया, जैसा कि अनुबंध आर-एल/2 से देखा जा सकता है। विश्वविद्यालय ने कॉलेज के प्राचार्य से स्पष्टीकरण भी मांगा था और बाद में प्राचार्य से यह बताने के लिए भी कहा था कि उन्होंने विश्वविद्यालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया और उम्मीदवार को प्रथम वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति क्यों दी। इस पृष्ठभूमि में, आशु सिंगली के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के अनुपात के आधार पर रोक की दलील वर्तमान मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होगी। याचिकाकर्ता, जिसने स्वीकार किया कि वह प्रवेश के लिए पात्र नहीं था, को अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इससे अन्यथा बड़ी संख्या में व्यक्तियों का अधिकार खत्म हो जाएगा, जो आवेदन कर सकते थे लेकिन उन्होंने यह सोचकर आवेदन नहीं किया कि वे पात्र नहीं हैं। आवेदन करने के लिए और. इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने अवैध रूप से जो लाभ प्राप्त किया वह कानून में अनुचित और अस्वीकार्य होगा।

(16) उसी नीबू पर। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि कॉलेज ने एक तरह से याचिकाकर्ता के जीवन के दो साल खराब कर दिए हैं। यदि कॉलेज याचिकाकर्ता की पात्रता की जांच करने के लिए पर्याप्त सतर्क होता और याचिकाकर्ता को प्रवेश नहीं देता, तो वह यहां अपना करियर बनाने में सक्षम हो सकता था। परिणाम यह हुआ कि याचिकाकर्ता ने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष खो दिये। निःसंदेह अकेले इलिस का कारण इस अवैधता को नजरअंदाज करने और याचिकाकर्ता को इस अध्ययन को जारी रखने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, हालांकि वह एलएलबी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए पात्र नहीं था। चूंकि याचिकाकर्ता ने कोई गलत बयानी नहीं की है और प्रथमदृष्ट्या यह कॉलेज ही है जो स्पष्ट रूप से इसके पक्ष में है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ छोटे-मोटे लाभों ने याचिकाकर्ता को एलएलबी में दाखिला दे दिया हैयह स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार याचिकाकर्ता को जीवन और करियर खराब करने के लिए निश्चित रूप से मुआवजा देने के लिए कॉलेज को निर्देश देने में एक अच्छी आसानी हो गई है। 'तदनुसार, कॉलेज को न केवल इन सभी वर्षों के लिए याचिकाकर्ता से ली गई पूरी ट्यूशन फीस वापस करनी होगी, बल्कि इसके अलावा याचिकाकर्ता को रुपये की दर से मुआवजा भी देना होगा। याचिकाकर्ता के जीवन और करियर को इतने समय तक विलंबित करने के लिए तीन साल की कुल अवधि के लिए 50,000 प्रति वर्ष। इस प्रकार, कॉलेज रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा। कॉलेज ने याचिकाकर्ता के जीवन को जो नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए मुआवजे/क्षति के रूप में 1,50,000 रु. इसके अलावा, यदि याचिकाकर्ता को लगता है कि उसके जीवन और करियर को हुई हानि और क्षति ऊपर आकलन से अधिक है, तो वह उचित मंच पर जाकर अतिरिक्त हर्जाना मांगने के लिए स्वतंत्र होगा, जो मुआवजा/क्षति प्रदान करते समय राशि को ध्यान में रखेगा। जैसा कि इस अदालत द्वारा याचिकाकर्ता को हुए नुकसान का आकलन करते समय, यदि कोई हो, देय पाया गया।

(17) उपरोक्त शर्तों के अनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
कुरुक्षेत्र